वैश्विक वामपंथ को निराशा के माहौल से बाहर निकालना होगा: छियालीसवाँ न्यूज़लेटर (2026)



खानाबदोश, बतजारगल बातरज़ोरिग (मंगोलिया), 2014

प्यारे दोस्तो,

ट्राईकॉन्टिनेंटल : सामाजिक शोध संस्थान की ओर से अभिवादन।

इस साल की शुरुआत में राजनीति का पलड़ा एक **ख़ास क़िस्म के चरम दक्षिणपंथ** और उसके **अति-साम्राज्यवादी** मंसूबों की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा था। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) ने **ब्लिट्ज़क्रीग** (बिजली की तरह तेज़) अभियान वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ छेड़ा और वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदूरो और उनकी पत्नी तथा राष्ट्रीय असेंबली सदस्य सीलिया फ़्लोरेस को अगवा कर लिया, उन्हें ग़ैर-क़ानूनी रूप से न्यूयॉर्क में बंदी बनाकर रखा गया है, और नतीजतन इस देश का तेल यूएस की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में आ गया। इसके लगभग दो महीने बाद यूएस और इज़राइल ने **ईरान के विरुद्ध आक्रामक युद्ध** शुरू कर दिया, जो वेनेज़ुएला के घटनाक्रम

का ही दोहराव लगा। लेकिन फ़ारस की खाड़ी में स्थित यूएस के सैन्य अड्डों और इज़राइल पर ईरान के हमलों ने दुनिया में शक्ति के संतुलन को पलट दिया और अति-साम्राज्यवाद की सैन्य ताक़त की कमज़ोरियों को उजागर कर दिया।

वेनेज़ुएला में सैन्य हमले के बाद सभी लैटिन अमेरिकी देशों को हड़पने की ट्रम्प की भूख इतनी बढ़ गई कि वह पूरी दुनिया को ही लील लेना चाहती थी। लेकिन ईरान के जवाब ने उन्हें लैटिन अमेरिका की ओर लौटा दिया, जहाँ उन्होंने अपना ध्यान **ग़ुस्से की लहर** को भड़काने पर केंद्रित किया। कोस्टा रीका, पेरू और कोलंबिया के चुनावों में चरम दक्षिणपंथ को जीत मिली, लेकिन उनके लिए असली इनाम तो हमेशा से ही ब्राज़ील रहा है – लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश, जिसका भूभाग आधे दक्षिण अमेरिका जितना है। 4 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव के बाद लगा कि ब्राज़ील में भी मौजूदा राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा को चरम दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ़्लावियो बोलसोनारो से हार झेलनी पड़ेगी। लेकिन 25 अक्टूबर को हुए दूसरे चरण के चुनावों में बोलसोनारो जीत न जाए इसके लिए ब्राज़ील के लाखों लोग लामबंद हुए और आख़िर में लूला की **जीत** हुई। लूला की जीत ने लैटिन अमेरिका में 'एंग्री टाइड' (आक्रामक दक्षिणपंथी लहर) के ख़िलाफ़ एक अहम सामाजिक-लोकतांत्रिक सुरक्षा घेरे का निर्माण किया। अगर बोलसोनारो की जीत होती तो इस महाद्वीप की प्रतिक्रियावादी ताक़तों का मनोबल बढ़ता और ब्राज़ील तथा उसके बाहर भी नव-नाज़ी रुझान को बढ़ावा मिलता। इसलिए यह चुनावी नतीजा बहुत मायने रखता है। लोकतांत्रिक परिस्थितियाँ, सार्वजनिक संस्थान और सामाजिक सुरक्षा मज़दूर वर्गीय संगठनों के लिए भौतिक परिस्थितियों का काम करते हैं। यह कहकर इनकी रक्षा करना छोड़ा नहीं जा सकता कि ये समाजवाद के लिए संघर्ष से ध्यान भटकाना है।



शहरी जीवन, ओस्मंड वॉटसन (जमैका), 1968

लूला की जीत ऐसे समय में हुई जब **भारत** और **यूरोप** में सरकारी ख़र्च में कटौती के ख़िलाफ़ और सामाजिक न्याय के लिए विशाल प्रदर्शन हो रहे हैं। इन घटनाओं के इतिहास और संभावनाएँ अलग-अलग हैं, लेकिन ये हमें मजबूर करती हैं कि विश्वभर में वामपंथ में जो हताशा छा गई है उसके बारे में दोबारा सोचा जाए। नवंबर की शुरुआत तक, नई संभावना का केंद्र यूएस की ओर खिसक गया, जहाँ ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनावों में निर्णायक हार मिली है। इस हार ने यूएस अति-साम्राज्यवाद की आकांक्षाओं को झटका दिया है क्योंकि इसने उन संस्थानों के बीच खाई को और गहरा कर दिया है जिनके ज़रिए यूएस सत्ता काम करती है। बजट, जाँच-पड़ताल और राजनीतिक अधिकार को लेकर होने वाले मतभेद अब ट्रम्प सरकार के लिए आगे की राह को पेचीदा कर देंगे।

ये दरारें टकराव की आशंका तैयार करती हैं, ख़ासतौर से इसलिए कि अब यूएस कांग्रेस में आठ सदस्य ऐसे होंगे जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ़ अमेरिका से जुड़े हैं। इन प्रतिनिधियों की औसत उम्र 38 साल है (सबसे छोटी मेलाट किरोस 29 वर्ष की हैं और सबसे बड़े क्रिस राब 56 वर्ष के)। अगर वे डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व की युद्ध और मितव्ययिता की राजनीति की राह पर चलते हैं, तो उन्हें ज़मीनी स्तर की ताक़तों के दबाव का सामना करना पड़ेगा। ये ताक़तें युद्ध से ऊब चुकी आम जनता की भावना को उन संस्थाओं और हितों के ख़िलाफ़ माँगों में बदल सकती हैं, जो युद्ध को बनाए रखते हैं।



शीर्षकहीन, डोमिनिक ज़िंक्पे (बेनिन), 2011

दक्षिण अफ़्रीका में 1994 के बाद पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी (SACP) ने अपने नाम से और अकेले लोकतांत्रिक चुनाव लड़ा। SACP ने अपनी उम्मीद से भी परे 7,00,000 से ज़्यादा वोट **हासिल** किए और देशभर में 260 से ज़्यादा सीटें जीती हैं। ख़ुद को एक मज़दूर वर्ग की पार्टी मानने वाली पार्टी का चुनावी दावा करना एक सबसे अहम राजनीतिक घटना है। SACP का **घोषणापत्र** बिजली, रोज़गार, आवास, और पानी के सवालों को संपत्ति के स्वामित्व, पूँजी और सत्ता के साथ जोड़ता है। SACP के चुनावी हस्तक्षेप ने एक अफ़्रीकी वामपंथ के लिए **राजनीतिक जगह** बनाने में मदद की है। एक ऐसा अफ़्रीकी वामपंथ जो सामाजिक मुक्ति को राष्ट्रीय संप्रभुता से जोड़ता है और जो बुर्किना फ़ासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे सहित **अलायंस ऑफ़ साहेल स्टेट्स** द्वारा अभिव्यक्त साम्राज्यवाद-विरोधी अभिलाषाओं के साथ खड़ा होने से घबराता नहीं। इस तरह की एकजुटता के लिए ज़रूरी है राजनीतिक सहभागिता और स्वतंत्र फ़ैसले।

भारत में छात्रों और श्रमिकों का विद्रोह ताक़त बटोर रहा है और एशिया तथा अफ़्रीका के अन्य हिस्सों में प्रतिध्वनित हो रहा है, क्योंकि किसान और अन्य उत्पीड़ित समुदाय इस अवसर के महत्त्व को महसूस कर रहे हैं। ब्राज़ील का उदाहरण इन अनुभवों के बीच से सीधे गुज़रता है : यह दर्शाता है कि अति दक्षिणपंथ को हराया जा सकता है। यह तथ्य उन लोगों के लिए मायने रखता है जो दमन और बार-बार मिली निराशा से हताश हैं। जब लूला की जीत की ख़बर किसी मीटिंग में बैठे व्यक्ति तक पहुँचती है, या काम की किसी जगह पर लोगों को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करती है, या किसी गाँव को अपना संघर्ष एक और हफ़्ते के लिए जारी रखने के लिए हौसला देती है तो आत्मविश्वास एक भौतिक शक्ति बन जाता है।

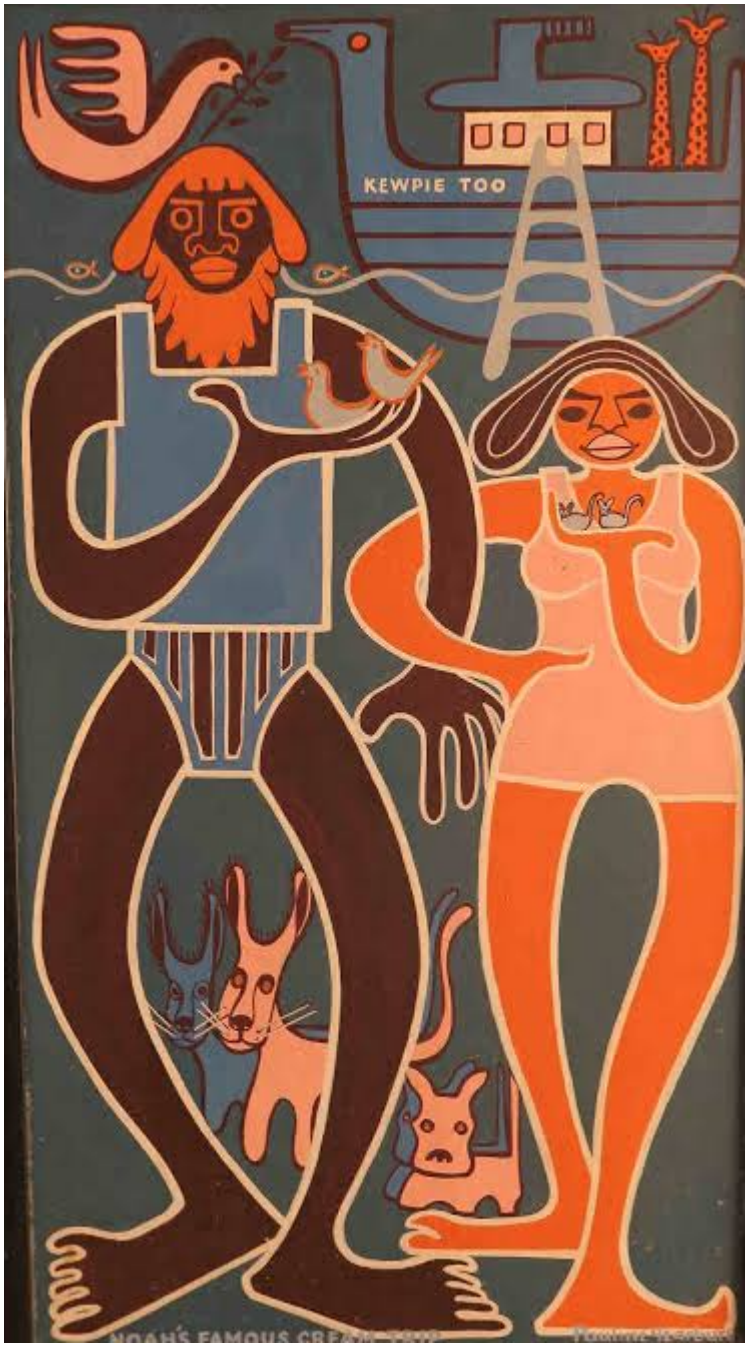


क्या यह इतना सरल और आसान है?, इवान सगिता (इंडोनेशिया), 2014

सालों से हमारे सामने एक बात साफ़ रही है कि भौतिक परिस्थितियाँ दक्षिणपंथ के मुक़ाबले वामपंथ के पक्ष में हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने *[illegible] 2026* (एक क़र्ज़ की दुनिया) नाम की एक आवश्यक **रिपोर्ट** छापी है जो दिखाती है कि साल 2025 में विकासशील देशों ने 995 अरब अमेरिकी डॉलर सार्वजनिक ऋण के ब्याज के रूप में चुकाए। कई विकासशील देशों में, जिनकी कुल आबादी 3.7 अरब है, कर्ज़ का ब्याज चुकाने में शिक्षा (20 देशों में) या स्वास्थ्य (46 देशों में) पर होने वाले खर्च से भी अधिक पैसा खर्च होता है। इनमें कई देश ऐसे हैं, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों पर होने वाला खर्च ब्याज चुकाने के खर्च से कम है। क़र्ज़दाता अपनी किस्ते माँगते हैं भले ही हमारे देशों में बच्चे बिना शिक्षकों की कक्षाओं में बैठे रहें और बिना दवाओं के मरीज़ परेशान होते रहें। UNCTAD का अनुमान है कि अगर विकासशील देशों को उन दरों पर क़र्ज़ मिलता जिनपर विकसित देशों को मिलता है तो वे

सालाना 500 अरब डॉलर बचा सकते हैं। जिन देशों को निवेश की ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें उसकी ऊँची क़ीमत चुकानी पड़ती है और फिर इन्हें उन क्षेत्रों में व्यय को नीचे लाना पड़ता है जिनसे इनकी जनता की रहन-सहन की परिस्थितियाँ सुधर सकती हैं और इनकी उत्पादक क्षमता मज़बूत हो सकती है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की अक्टूबर 2026 की विश्व आर्थिक परिदृश्य **रिपोर्ट** इनमें से कुछ तथ्यों को दर्ज करती है और फिर सरकारों से जीवन-यापन संकट के दौरान अस्थायी, लक्षित आय सहायता प्रदान करने का आग्रह करती है। एक अस्थायी भुगतान ज़रूरी है, लेकिन अपर्याप्त भी। मानवता को ऐसी सार्वजनिक व्यवस्थाओं की ज़रूरत है जो आवश्यक वस्तुओं की गारंटी दे सकें, प्रत्यक्ष निवेश कर सकें, और अस्थिर बाज़ारों पर निर्भरता कम कर सकें। **अति-उदारवादी** भी इन मुद्दों का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि वे ऐसे आर्थिक ढाँचे का बचाव करते हैं जो सार्वजनिक प्रावधान को निजी संचय के अधीन कर देता है और तब हैरानी जताते हैं जब उसके शिकार लोग उसे प्रशासित करने वाली संस्थाओं में विश्वास खो देते हैं। उस समय, वे लोगों से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कहते हैं, भले ही उन्होंने उन आर्थिक विकल्पों को सीमित कर दिया है जिन्हें लोकतंत्र को चुनने की अनुमति है। इस सबके बीच एक ख़ास क़िस्म का चरम दक्षिणपंथ इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए एक नक़ली बगावत के साथ दाखिल होता है। यह लोगों के ग़ुस्से को प्रवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और वामपंथ की ओर मोड़ देता है, ताकि बैंकों, ज़मीन और बड़े-बड़े निगमों के मालिकों की सत्ता सुरक्षित बनी रहे।



नोआ की प्रसिद्ध क्रीम यात्रा, पॉलीन काहुरंगी यर्बरी (आओतेआरोआ), 1966

वर्षों से हम सवाल करते आए हैं कि आख़िर मज़दूर वर्ग चरम दक्षिणपंथ की ओर क्यों आकर्षित हो रहा है और उनके सामने एक विकल्प के रूप में खड़ा होने तथा अपनी ताक़त बढ़ाने के लिए वामपंथ को क्या करना चाहिए। कामगार जनता न तो हमेशा प्रतिक्रियावादी होती है और न ही अपने-आप क्रांतिकारी बन जाती है। संघर्षों, हमारे पास मौजूद संगठनों और इस अनुभव के आधार पर हमारी राजनीतिक दिशा तय होती है कि सामूहिक प्रयासों से हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं या नहीं।

इसलिए अपनी ताक़त जुटाने के ठोस मायने हैं, जिसकी शुरुआत होती है मज़दूर यूनियनों और किसान संगठनों, महिला मंचों और युवाओं के समूहों, शोषितों और हाशिए पर धकेले गए लोगों के आंदोलनों को इकट्ठा करने से। कई दफ़ा दुनिया के अप्रत्याशित कोनों में छिपी इन ताक़तों को रोज़ाना एक-दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा विश्लेषण भी

इनकी ज़रूरत है जो निराशावाद से परे जाता हो और हमें दिखाए कि दुनिया सही में गतिमान है। **अंतरराष्ट्रीय पीपल्स असेंबली** इसी के निर्माण का काम कर रही है और ट्राईकॉन्टिनेंटल : सामाजिक शोध संस्थान इसी का अध्ययन और लेखन कर रहा है। आप **IPA के न्यूज़लेटर** और हमारे **साप्ताहिक न्यूज़लेटर** को सब्स्क्राइब ज़रूर करें। अगर आप किसी आंदोलन का हिस्सा हैं, तो **IPA से संपर्क करें** और जानें कि कैसे आप इसके अंतरराष्ट्रीय अभियानों से जुड़ सकते हैं।



पतंग, ग़जबिया सिरी (मिस्र), 1960

हम एक वामपंथी कार्यक्रम तैयार करने के लिए विश्लेषण का काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत वर्तमान में ही लोगों का जीवन बेहतर बनाने और हासिल की गई सामाजिक सफलताओं की रक्षा करने से होगी। इसके बाद यह एक समाजवादी भविष्य में तब्दील होगा जिसका आधार होगी लोकतांत्रिक योजना के तहत विकसित हुई उत्पादक शक्तियाँ। हमारे सामने एक बात स्पष्ट है कि जैसा भी कार्यक्रम हो इसके केंद्र में शांति और साम्राज्यवाद-विरोध के विचार होने चाहिए। युद्धों से उत्पादक क्षमता नष्ट होती है, जीवन निर्वाह की लागत (कॉस्ट ऑफ़ लिविंग) बढ़ती है और संसाधन मानव विकास के बजाय अन्य क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। दुनियाभर में चल रहे संघर्षों के लिए ज़रूरी है कि आंदोलनों में आपसी सहयोग बने और सरकारें क़र्ज़दाताओं के विशेषाधिकारों और साम्राज्यवादी ताक़तों के दबाव को चुनौती देने की इच्छा रखती हों।

इस काम के लिए कोई एक चुनावी फार्मूला नहीं है। किसी देश में चरम दक्षिणपंथ से लड़ने के लिए शायद एक व्यापक गठबंधन बनाने की ज़रूरत हो। तो दूसरे किसी देश में मज़दूर वर्ग की आवाज़ को फिर से बुलंद करने के लिए एक स्वतंत्र कम्युनिस्ट हस्तक्षेप अनिवार्य हो सकता है। कसौटी यह है कि कोई रणनीति जन-संगठन को मज़बूत करती है या नहीं और अगले चुनाव से आगे बढ़कर **कार्य करने की क्षमता** को आगे बढ़ाती है या नहीं। गठबंधनों को इस आधार पर आँका जाना चाहिए कि वे किन सामाजिक शक्तियों को गतिशील करते हैं, किन प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करते हैं, और आगे के संघर्ष के लिए कितनी गुंजाइश पैदा करते हैं। हमारे अंतरराष्ट्रीयतावाद को इन मौजूद अनुभवों को एक-दूसरे के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए, लेकिन यह नहीं मान लेना चाहिए कि ब्राज़ील का तैयार मॉडल भारत में चल जाए या दक्षिण अफ़्रीका के चुने गए विकल्पों को पूरे महाद्वीप में लागू किया जाए, जबकि इस महाद्वीप में अलग-अलग मुक्ति संघर्षों के इतिहास हैं और वर्गीय शक्ति के लिए अपने-अपने अधूरे संघर्ष भी। हमारे सामने जो भी संभावनाएँ हैं वे प्रगति की कोई भी गारंटी नहीं देती। बल्कि इनमें से हरेक संगठित शक्तियों पर एक ज़िम्मेदारी डालती हैं। सवाल यह है कि क्या वामपंथ, राहत को विश्वास में, विश्वास को संगठन में, और संगठन को एक सतत शक्ति में बदल सकता है या नहीं। दुनिया गतिशील है। हमें भी अपने लोगों के साथ गतिशील होना होगा, एक ऐसे कार्यक्रम के साथ जिसे वे अपना बना सकें।

इसी सोच के साथ, आपके साथ अपने एक कविता साझा कर रहा हूँ, शीर्षक है 'एक सदी, एक संघर्ष' :

> खदान और मिल से, गन्ने के खेतों से,
>
> वे आ रहे हैं सोने का शासन उखाड़ फेंकने,
>
> रोटी हासिल करने को, पीड़ा ख़त्म करने को,
>
> एक दुनिया गढ़ने को जिसका कोई राजा नहीं।
>
> सौ साल : झंडे लहराते रहे,
>
> फिर भी खेती करने वालों के हाथ बँधे रहे क़र्ज़ से।
>
> फल उनके, बीज हमारे।
>
> लहराती फसलों के बीच हमारे बच्चे भूखे रहे।

> कोई राजा इस दुनिया को नहीं देगा उसके हक़ की रोटी।
>
> कोई बम किसी बीज को उगना नहीं सिखा सकता।
>
> जिन्होंने ख़्वाब देखा और ख़ून बहाया, हम बढ़ रहे हैं उनके साथ
>
> अजन्मे राष्ट्रों को उनकी जगह देने के लिए।

स्नेह सहित,

विजय